



# 3 लाख में मिलेगा फ्लैट

संवाददाता

रूद्रपुर/देहरादून। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि धामी सरकार की जनता को बड़ी सौगात है मात्र तीन लाख रुपये में आधुनिक फ्लैट मिलेंगे।

आज यहां सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के संकल्प के साथ उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार मिलकर एक ऐसी आवासीय परियोजना को अंतिम रूप दे रही हैं, जो हजारों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रूद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सतत निगरानी में विकसित यह परियोजना राज्य में गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (उधमसिंह नगर) द्वारा संचालित इस



महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अब तक पक्का मकान नहीं है।

परियोजना के पूर्ण होने के बाद हजारों लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। 'अपना घर, अपना स्वाभिमान' की भावना के साथ तैयार की गई इस परियोजना में कुल 1872 आवासों का निर्माण किया गया है। इनमें से 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं,

जबकि 512 अतिरिक्त फ्लैटों में अंतिम चरण के छोटे-मोटे कार्य तेजी से चल रहे हैं।

सरकार की योजना शीघ्र ही परियोजना का लोकार्पण कर लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि छह लाख रुपये लागत वाले इन आधुनिक फ्लैटों के लिए लाभार्थी को मात्र तीन लाख रुपये ही देने होंगे। शेष राशि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़

लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इससे सीमित आय वाले परिवारों को भी सम्मानजनक आवास प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

करीब 6.0281 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस आवासीय परियोजना का निर्माण क्षेत्रफल लगभग 39,220 वर्ग मीटर है। योजना में कुल 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें आधुनिक शहरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक फ्लैट में एक

बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा उपलब्ध कराया गया है। लगभग 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इन आवासों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि छोटे परिवारों को पर्याप्त सुविधा और बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

परियोजना की विशेषता यह है कि सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही चौड़ी सड़कों, पर्याप्त पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। बागवाला आवासीय परियोजना को केवल मकानों का समूह नहीं, बल्कि एक आधुनिक और टिकाऊ आवासीय परिसर के रूप में विकसित किया गया है।

परिसर में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), सीवरेज सिस्टम और अत्याधुनिक एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की व्यवस्था की गई है। परियोजना में हरे-भरे पार्क, बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र और सौंदर्यीकरण के व्यापक कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। हॉर्टिकल्चर का कार्य पूर्ण होने से परिसर का वातावरण आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल बन गया है।

# निहंगों के आने की सूचना पर सीमाएं सील

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड में निहंगों के जत्थे आने की सूचना पर प्रशासन द्वारा सर्तकता बरतते हुए सीमाएं सील कर दी गयी है। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गयी है।

बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व उत्तराखण्ड के रूद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित दमदमा साहिब गुरुद्वारे में कुछ निहंगों द्वारा विवाद की स्थिति पैदा कर दी गयी थी। निहंगों ने वहां मौजूद दो लोगों को बंधक बना लिया था। जिनकी मांग थी कि कर्णप्रयाग में निहंगों के साथ हुए विवाद में जिन निहंगों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाये। चार दिन यानि



शनिवार से चले इस विवाद के बाद बीते मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे पंजाब से आये प्रतिनिधि मंडल ने गुरुद्वारे

के भीतर जाकर निहंगों से बातचीत की। इस दौरान पुलिस व प्रशासन द्वारा भी मध्यस्ता की गयी। कुछ देर चली वार्ता

के बाद निहंग शांतिपूर्व ढंग से बाहर आ गये जिन्हें पंजाब भेज दिया गया। वहीं अभी मामला शांत ही हुआ था

कि आज एक बार फिर प्रशासन को सूचना मिली कि कुछ निहंगों के जत्थे उत्तराखण्ड में प्रवेश करने वाले है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रशासन सर्तक हो गया और बार्डर पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गयी।

समाचार लिखे जाने तक निहंगों का कोई भी जत्था उत्तराखण्ड बार्डर पर नहीं पहुंचा था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन को मिली यह सूचना सही हो सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसी गुरुद्वारे में काफी संख्या में निहंग मौजूद दिख रहे है।

## दून वैली मेल

संपादकीय

### आस्था की लूट-खसोट का आशय

आज शायद अपनी बात 6 दशक पूर्व 1971 में आई हिंदी फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण के उस गीत से 'देखो ए दीवानो यह काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, से करना ही सबसे उचित होगा। अपने समय के मशहूर गायक किशोर कुमार का यह गीत वर्तमान दौर के हमारे राजनीतिक और सामाजिक हालात पर सटीक साबित हो रहा है। इन दिनों अयोध्या में बने राम मंदिर से करोड़ों रुपए के दान चोरी का मामला सबसे अधिक चर्चाओं में है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के अन्य तमाम मामले जैसे मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव का वह जमीन खरीद का मामला जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है यह बताया गया है कि कैसे एक सूबे के सीएम ने अपने उन 37 नाते रिश्तेदारों और परिजनों के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है उल्लेख किया गया है तथा उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सरकारी जमीन की खरीदने की धाधली हुई। जैसे अनेक मामले चर्चाओं के केंद्र में हैं। देश की सत्ता में बैठे लोगों द्वारा देश भर में जिस तरह से देश के संसाधनों और खजाने की लूट-खसोट की जा रही है और राम के नाम तथा धार्मिक स्थलों को सुनियोजित ढंग से अपने कब्जे में लिया जा रहा है इसका सच वास्तव में हैरान करने वाला है। हिंदी के महान कवि गजानन मुक्ति बोध की एक कविता अंधेरे में जो लिखा गया है उसमें रात निकलने वाले एक जुलूस में शामिल लोगों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के छठैत (गुंडे-बदमाशों) की मौजूदगी का वर्णन किया गया है। ठीक वैसा ही परिदृश्य आज अपने देश में दिखाई दे रहा है। जिस आस्था के केंद्र राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी थी इस राम मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा दान के खजाने को लूटने का जो काम किया गया है तथा अब एसआईटी गठन के जरिए उस पर लीपा पोती की जा रही है वह वास्तव में बेशर्मी की इंतहा ही है। इस मामले की रिपोर्ट एसआईटी द्वारा संजय प्रसाद को सौंपी गई है वह संघी तो है ही साथ ही वह खुद भी राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों में शामिल है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जांच का क्या नतीजा निकल सकता है। यह लूटपाट की कहानी किसी एक धार्मिक स्थल या आस्था केंद्र की नहीं है उत्तराखंड में अभी विगत दिनों मुंबई के एक बड़े व्यवसायी द्वारा केदारनाथ मंदिर को बहुत सोना दान किए जाने और गर्भ ग्रह को स्वर्ण जनित्र बनाने के लिए सोना दिया गया था जिसमें सोना चोरी होने और गर्भ ग्रह में सोने की जगह मिश्रित धातु की सोने के पानी वाली परत चढ़ाई जाने की बात सामने आई थी इसकी जांच कराई गई थी लेकिन इसकी हकीकत आज तक सामने नहीं आ सकी है। हो सकता है अयोध्या के राम मंदिर में दान की डकैती का मामला भी कल इसी तरह रफा दफा हो जाए। लेकिन इस घटना ने राम भक्तों और सनातन को मानने वालों की जहनियत को झकझोर कर रख दिया है। खास बात ही है न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे लोक लुभावन जुमले उछालने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में आज अगर चंपत राय का नाम शामिल है वही इस ट्रस्ट में दर्जन भर लोग ऐसे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघ और भाजपा मिलकर मोदी की छवि को एक विश्व गुरु ही नहीं एक धर्मगुरु के रूप में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। पीएम का अपने आप को नान बायोलॉजिकल होने का बयान भी इसकी पुष्टि करता है साथ ही अभी प्रकाश में आई एक रिपोर्ट जिसमें उनकी धर्मगुरु की छवि गढ़ने पर 2000 करोड़ का खर्च होने की बात सामने आई है। जिसका मकसद सिर्फ आस्था के नाम पर वोट बटोरना ही है। देश व समाज में क्या हो रहा है? इस पर पाठक खुद चिंतन करें तो ज्यादा बेहतर होगा।

### डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो होगा डीएम का घेराव:गौड



संवाददाता

देहरादून। डीएवी कालेज के पूर्व महासचिव आकाश गौड ने महिला की मौत पर हास्पिटल डॉक्टरों व स्टाफ पर कार्यवाही न होने पर चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिलाधिकारी का घेराव किया जायेगा। आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए आकाश गौड ने कहा कि बसंत विहार क्षेत्र के हास्पिटल की लापरवाही से जच्चा-बच्चा की मौत को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच कमेटी बैठायी गयी उनके द्वारा जांच की गयी। नर्सिंग होम की लापरवाही को देखते हुए नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। परन्तु अभी तक डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जांच कमेटी से मांग की है कि यदि एक हफ्ते के भीतर वहां से डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तो वह जिलाधिकारी का घेराव करेंगे।

## 'मुद्दे' गायब और बयानों में 'उबाल'

कार्यालय संवाददाता  
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में काफी समय शेष है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी गमरग अंधी से महसूस की जाने लगी है। विकास, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बहस होने के बजाय राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेताओं की भाषा में बढ़ती तलखी इस बात का संकेत है कि चुनावी रणभूमि की तैयारी शुरू हो गई है।

हाल के दिनों में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल पर हमलों की धार तेज कर दी है। भाजपा नेताओं का दावा है कि विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है और इसलिए वह केवल सरकार की आलोचना तक सीमित है। दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। कई मौकों पर कांग्रेस नेताओं के बयान सीधे प्रधानमंत्री तक को निशाने पर लेते दिखाई दिए हैं। जवाब में भाजपा इसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर हमला बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा चाहती है कि चुनावी विमर्श राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रवाद और केंद्र सरकार की योजनाओं के इर्द-गिर्द घूमे। वहीं कांग्रेस कोशिश कर रही है कि चुनाव को स्थानीय मुद्दों और सरकार विरोधी भावनाओं

●नेताओं को एक-दूसरे की कमियां गिनाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही  
●चुनावी मौसम आने वाला है, इसलिए मुद्दे नहीं, बयान उगलने लगे नेता  
●भाजपा-कांग्रेस और यूकेडी पर हमलावर, कांग्रेस के निशाने पर प्रधानमंत्री तक

पर केंद्रित किया जाए। यूकेडी क्षेत्रीय अस्मिता और राज्य आंदोलन की मूल भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है। दिलचस्प बात यह है कि चुनावी माहौल गर्म करने में सोशल मीडिया की भूमिका भी तेजी से बढ़ी है। नेताओं के भाषणों के छोटे-छोटे वीडियो क्लिप, बयान और प्रतिक्रियाएं कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच रही हैं। राजनीतिक दल जानते हैं कि आज की राजनीति में बयान केवल सभा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दूर-दराज के गांवों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि हर बयान अब एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश बनता जा रहा है।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता भी इसी प्रकार की राजनीति चाहती है? प्रदेश के सामने आज भी बेरोजगारी, पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आपदा प्रबंधन जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। पहाड़ के खाली होते गांव, युवाओं के रोजगार का संकट और बढ़ती शहरी अव्यवस्थाएं ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ठोस बहस की अपेक्षा की जाती है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों की प्राथमिकता फिलहाल एक-दूसरे पर हमले

करने में अधिक दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी का स्तर और अधिक तीखा हो सकता है। पिछले चुनावों का इतिहास भी यही बताता है कि जैसे-जैसे मतदान का समय करीब आता है, व्यक्तिगत आरोप, राजनीतिक कटाक्ष और जुबानी हमले बढ़ने लगते हैं। इस बार भी उसके संकेत समय से पहले दिखाई देने लगे हैं।

भाजपा के लिए चुनौती दस वर्षों की सत्ता के बाद जनता के विश्वास को बनाए रखने की है। कांग्रेस के सामने खुद को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित करने की चुनौती है। वहीं यूकेडी और अन्य छोटे दल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी दलों को लगता है कि आक्रामक राजनीति उन्हें चर्चा में बनाए रख सकती है।

हालांकि लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और राजनीतिक बहस जरूरी मानी जाती है, लेकिन जब बहस मुद्दों से हटकर केवल आरोपों और व्यक्तिगत हमलों तक सीमित हो जाए तो जनता के वास्तविक सरोकार पीछे छूटने लगते हैं। उत्तराखंड की राजनीति इस समय ठीक उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल दी हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में चुनावी चर्चा विकास और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित होती है या फिर आरोप-प्रत्यारोप की यह राजनीति ही पूरे चुनावी विमर्श पर हावी रहती है।

## भाजपा का 'ब्रह्मास्त्र' बनेगा कार्यकर्ता

कार्यालय संवाददाता  
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की आहट ने भाजपा के भीतर संगठनात्मक समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। सत्ता के गलियारों में प्रभावशाली नेताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच खड़ा वह साधारण कार्यकर्ता, जो पिछले कुछ वर्षों में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था, अचानक भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बन गया है। पार्टी नेतृत्व अब गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रखने वाले कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति का केंद्र बना रहा है।

भाजपा अच्छी तरह समझती है कि चुनावी जीत केवल सरकारी योजनाओं, बड़े नेताओं की सभाओं और सोशल मीडिया अभियानों से सुनिश्चित नहीं होती। बूथ पर बैठा कार्यकर्ता ही वह कड़ी है जो मतदाता और पार्टी के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। यही कारण है कि संगठन अब बूथ समितियों को सक्रिय करने, पन्ना प्रमुखों को मजबूत करने और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से मैदान में उतारने की कवायद में जुट गया है।

दरअसल, सत्ता के दस वर्षों के दौरान पार्टी के भीतर एक धारणा बनी कि कुछ चुनिंदा नेताओं और पदाधिकारियों तक ही संगठन सीमित हो गया है। कई पुराने कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक और निजी तौर पर यह शिकायत भी की कि उन्हें

□सत्ता विरोधी माहौल की आशंकाओं के बीच बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की कवायद तेज  
□गांव-गांव में सक्रिय किए जा रहे भाजपा के जमीन से जुड़े पुराने सभी कार्यकर्ता  
□संगठन के दरवाजे पर इंतजार करने वाले कार्यकर्ता बनेंगे चुनावी वैंटरणी पार कराने वाले

न तो संगठन में पर्याप्त महत्व मिला और न ही सरकार में उनकी सुनवाई हुई। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी को एहसास हो रहा है कि चुनावी जंग एयरकंडीशंड कमरों में नहीं, बल्कि गांव की चौपालों, कस्बों की गलियों और बूथों पर लड़ी जाती है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने हाल के दिनों में लगातार संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला तेज किया है। मंत्रियों, विधायकों और जिलाध्यक्षों को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि बूथ स्तर तक संवाद बढ़ाया जाए। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि विपक्ष के आरोपों, स्थानीय नाराजगियों और सरकार विरोधी माहौल को निष्प्रभावी करने का काम केवल वही कार्यकर्ता कर सकता है जो रोज जनता के बीच रहता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका कैंडर आधारित ढांचा रहा है। 2017 और 2022 के चुनावों में भी बूथ प्रबंधन ने

पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई थी। लेकिन इस बार चुनौती अलग है। एक ओर सत्ता विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करना है तो दूसरी ओर संगठन के भीतर नाराज कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व छोटे कार्यकर्ता को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन कार्यकर्ताओं को कभी नेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने तक सीमित समझा जाता था, आज वही कार्यकर्ता चुनावी गणित के सबसे अहम सूत्रधार बन गए हैं। गांवों में होने वाली बैठकों से लेकर सोशल मीडिया के स्थानीय नेटवर्क तक, हर जगह कार्यकर्ता की भूमिका बढ़ी है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी भाजपा की इस रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आते ही भाजपा को कार्यकर्ताओं की याद आ जाती है, जबकि सत्ता के दौरान उनकी उपेक्षा की जाती है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि संगठन की असली ताकत हमेशा कार्यकर्ता ही रहा है और रहेगा।

फिलहाल इतना तय है कि 2027 की चुनावी रणभेरी बजने से पहले भाजपा में सबसे अधिक पूछ-परख किसी मंत्री, विधायक या पदाधिकारी की नहीं, बल्कि उस कार्यकर्ता की हो रही है जो हर चुनाव में पार्टी का झंडा लेकर सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है।

## कहूखाल और धनोल्ती में पार्किंग निर्माण की धीमी रफतार पर डीएम नाराज

नई टिहरी (आरएनएस)। पर्यटक स्थल कहूखाल और धनोल्ती में निर्माणाधीन वाहन पार्किंग का डीएम नितिका खंडेलवाल ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहूखाल में धीमी गति से चल रहे निर्माण पर डीएम ने नाराजगी जताई। पार्किंग निर्माण कार्य में मात्र 12 श्रमिक लगे हुए मिले। कार्यदायी संस्था लोनिवि को मजदूरों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं धनोल्ती पार्किंग का निरीक्षण करते हुए डीएम ने एक माह के भीतर कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है। डीएम ने कहूखाल में निर्माणाधीन वाहन पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। लोनिवि थत्यूड के राजेंद्र प्रसाद टम्टा ने बताया कि 7.94 करोड़ से पार्किंग बनाई जा रही है जिसमें 106 वाहनों के खड़े होने की क्षमता है। नवंबर 2026 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। डीएम ने धीमी गति से चल रहे निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं। ईई को ठेकेदार से देरी के कारणों की आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा। बाद में डीएम ने धनोल्ती में निर्माणाधीन वाहन पार्किंग का निरीक्षण किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन तहत वहां 3.76 करोड़ रुपये की लागत से दो अलग-अलग पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग संख्या-दो का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है जबकि पार्किंग संख्या-एक में भूतल का कार्य पूर्ण होने के साथ प्रथम तल के लिए रैप और रेलिंग निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने एक माह के भीतर पार्किंग कार्य पूरा न होने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

## डाक विभाग की नीतियों के खिलाफ ग्रामीण डाक सेवकों का धरना

पौड़ी (आरएनएस)। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने ग्रामीण डाक सेवकों पर बढ़ते लक्ष्य आधारित दबाव और उत्पीड़न के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। संघ ने डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय में प्रधान डाकघर परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवकों ने सांकेतिक धरना दिया। कार्मिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। संघ के मंडलीय अध्यक्ष विजय नैथानी व मंडलीय सचिव प्रेम सिंह भंडारी ने बताया कि जनपद में प्रधान डाकघरों से लेकर ग्रामीण डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विपरीत परिस्थितियों में लगातार ग्रामीण डाक सेवक बेहतर सेवाएं दे रहे हैं लेकिन गत वर्षों से डाक विभाग में खाता खोलने और पीएलआई को लक्ष्य आधारित बना दिया गया है। लक्ष्य हासिल नहीं होने पर कार्मिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है जिससे कार्मिक तनाव में हैं। उन्होंने लक्ष्य को आधार बनाए जाने पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की। संघ ने ग्रामीण डाक सेवकों को आठवें वेतन आयोग में शामिल किए जाने, शाखा डाकघरों में स्टेशनरी की पूर्ति किए जाने, जीडीएस कार्मिकों को अवकाश दिए जाने पर उसे सेवा में जोड़े जाने सहित अन्य मांगों के समाधान की मांग की।

## ईरान-अमेरिका समझौते से हरिद्वार के निर्यातकों को राहत

हरिद्वार (आरएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम से हरिद्वार के निर्यातकों को राहत मिली है। जिले के निर्यातकों को जल्द स्थिति सामान्य होने और निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी उद्योगों में निर्यात के लिए उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है। समझौते के बाद निर्यातक वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी हुई है। वहीं, युद्ध के बीच देश में लागू गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के नियमों को वापस लेने की निर्यातक प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थिति सामान्य होने के बाद उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जाएगा। जिले से हैंडीक्राफ्ट, फूड, फार्मा, ऑटोमोबाइल, वेदर इंस्ट्रुमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड सेक्टर आदि का उत्पादन विदेशों में निर्यात होता है। जिले के सभी सेक्टर में करीब 900 करोड़ रुपये का सालाना निर्यात का अनुमान है। युद्ध के बीच जिले के उद्योगों से निर्यात 45 फीसदी तक घटा है। हरिद्वार से आटा, नूडल्स, मस्टर्ड ऑयल, पापड़, आचार, हर्बल उत्पादन, मसाले और आयुर्वेदिक खाद्य सामग्री खाड़ी सहित कई देशों में निर्यात होती है। समुद्री मार्ग का किराया बढ़ने से दिक्रें बढ़ी हुई है। उद्योगों का करंसी सर्कुलेशन भी रुका हुआ है। कई उद्योगों का माल दिल्ली कस्टम में पिछले तीन महीनों से रुका हुआ है। माल का निर्यात नहीं हो रहा है। गोदामों में भी तैयार माल रखा हुआ है। साथ ही समुद्री माल भाड़ा कम होने, लॉजिस्टिक्स में सुधार, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, गल्फ के बाजारों में सामानों की मांग बढ़ने से निर्यात को भारी लाभ होने की उम्मीद बनी है।

### वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो सांध्य दैनिक दून वैली मेल के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

## तिमला: जड़े मिट्टी में और यादें सीने में

कार्यालय संवाददाता  
देहरादून। उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय, नदियों और देवस्थलों से नहीं है, बल्कि उन पारंपरिक वृक्षों से भी है, जिन्होंने सदियों से पहाड़ के जीवन को सहारा दिया है। इन्हीं में से एक है तिमला। खेतों की मेड़ों, गांव के समीप, आंगन के आसपास और पगडंडियों के किनारे सहज रूप से उगने वाला यह वृक्ष पहाड़ के ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। एक समय ऐसा था जब शायद ही कोई गांव ऐसा होता, जहां तिमला का पेड़ न दिखाई देता हो। आज भी बुजुर्ग जब तिमला का नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं।

तिमला केवल फल देने वाला पेड़ नहीं है, बल्कि यह पहाड़ की आत्मनिर्भर जीवनशैली का प्रतीक है। पशुओं के लिए चारा, बच्चों के लिए प्राकृतिक मिठास, किसानों के लिए खेतों की सुरक्षा और ग्रामीणों के लिए घरेलू औषधि—एक ही पेड़ इतने रूपों में लोगों के काम आता है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। ऐसे में तिमला का महत्व और बढ़ जाता है। इसकी कोमल पत्तियां गाय, बैल, भैंस और बकरियों के लिए पौष्टिक चारे के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि तिमला का चारा खाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और दूध देने वाले पशुओं की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहाड़ में जहां वर्ष के कई महीनों तक हरा चारा सीमित होता है, वहां तिमला किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता।

गर्मियों के मौसम में जब तिमला पर छोटे-छोटे फल पकते हैं तो पूरा पेड़ मानो मिठास से भर उठता है। बाहर से साधारण दिखने वाला यह फल स्वाद में बेहद मीठा होता है। गांवों में बच्चे स्कूल जाते समय और लौटते वक्त पेड़ पर चढ़कर इसके फल खाते थे। उस समय न चॉकलेट का आकर्षण था और न पैकेट वाले स्नैक्स का, तिमला ही पहाड़ के बचपन की सबसे मीठी याद हुआ करता था। यह फल केवल स्वादिष्ट ही



नहीं, बल्कि पोषण से भी भरपूर माना जाता है। इसमें प्राकृतिक शर्करा, फाइबर और कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।

लोक चिकित्सा में तिमला का विशेष स्थान रहा है। ग्रामीण वैद्य और बुजुर्ग

● एक ऐसा वृक्ष जो पशुपालन, खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य का आधार रहा  
● गुम होती यादों के बीच आज भी अपनी माटी की महक देता तिमले का पेड़  
● पहाड़ में सुख-दुख बांटने के लिए सदियों से सभाला ग्रामीण जीवन का आंगन  
● आधुनिकता की चकाचौंध में धीरे-धीरे गांवों से हो रहा तिमले का पेड़ गायब

इसके फल, छाल और दूधिया रस का उपयोग विभिन्न पारंपरिक उपचारों में करते रहे हैं। माना जाता है कि इसका फल पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक होता है। इसकी छाल और दूधिया रस का सीमित उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं और अन्य पारंपरिक उपचारों में भी किया जाता रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि औषधीय उपयोग चिकित्सकीय सलाह के बाद ही किया जाना चाहिए।

तिमला खेतों की मेड़ों पर इसलिए लगाया जाता था क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं। इससे वर्षा के दौरान मिट्टी का कटाव कम होता है और खेत सुरक्षित रहते हैं। इसके पेड़ तेज धूप में किसानों और राहगीरों को छाया भी देते हैं। यह वृक्ष पर्यावरण

संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पक्षियों के लिए यह सुरक्षित आश्रय है और इसके फल कई जीव-जंतुओं का भोजन भी बनते हैं। इस तरह तिमला जैव विविधता की रक्षा में भी अपनी भूमिका निभाता है।

पलायन, घटती खेती, सीमेंट-कंक्रीट का बढ़ता विस्तार और पारंपरिक वृक्षों की अनदेखी ने तिमला की संख्या पर भी असर डाला है। पहले हर गांव में आसानी से दिखाई देने वाला यह वृक्ष अब कई स्थानों पर दुर्लभ होता जा रहा है। नई पीढ़ी इसके नाम से भी अनजान होती जा रही है। विडंबना यह है कि जिस दौर में पूरी दुनिया आर्गेनिक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की ओर लौट रही है, उसी समय पहाड़ अपनी प्राकृतिक धरोहरों को खोता जा रहा है।

यदि तिमला के फलों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण और प्रसंस्करण किया जाए तो इससे जैम, जेली, स्कवैश, सूखे फल और हर्बल उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। वन विभाग और कृषि विभाग यदि तिमला के पौधों का बड़े स्तर पर रोपण अभियान चलाएं तो यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे सकता है। पहाड़ में तिमला केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि लोकजीवन का हिस्सा है। इसकी छांव में चौपालें लगें, बच्चों का बचपन बीता और पशुपालकों का जीवन आसान हुआ। यह पेड़ पहाड़ की उस संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति और इंसान का रिश्ता केवल उपयोग का नहीं, बल्कि आत्मीयता का था।

## विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : भरत सिंह चौधरी

अल्मोड़ा (आरएनएस)। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जनपद में विकास योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक से पूर्व उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके

उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने जनपद में संचालित विकास योजनाओं, आजीविका संवर्धन, स्वरोजगार तथा अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने ग्राम स्तर तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा स्थानीय संसाधनों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने जनपद में बांस आधारित परियोजना को पायलट परियोजना के रूप में विकसित करने का

सुझाव देते हुए कहा कि इससे खेतों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही पर्यटन और होमस्टे योजनाओं को रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए लाभार्थियों को आतिथ्य संबंधी प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए जनहित में इसी प्रकार कार्य करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आश्चस्त किया कि मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गंगा बिष्ट, मेयर अजय वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



## गर्मियों में फूलों वाली स्कर्ट के साथ पहनें ये डिजाइनर टॉप, आपको मिलेगा खूबसूरत लुक

गर्मियों में फूलों वाली स्कर्ट पहनना एक बेहतरीन विकल्प है। ये न केवल आपको टंडक देती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाती हैं। अगर आप सोच रही हैं कि इन स्कर्ट के साथ कौन-सा टॉप पहनें तो चिंता न करें। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसे डिजाइनर टॉप के बारे में बताएंगे, जो फूलों वाली स्कर्ट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और आपके लुक को खास बना सकते हैं।

**सफेद शर्ट-** सफेद शर्ट हमेशा से ही एक अच्छा विकल्प रही है। यह न केवल आरामदायक होती है, बल्कि किसी भी प्रकार की स्कर्ट के साथ अच्छी लगती है। यह आउटफिट आपको एक पेशेवर लुक भी दे सकता है, जो ऑफिस मीटिंग के लिए बढ़िया रहेगा। यह संतुलित लुक देता है और आपके पूरे लुक को खास बनाता है। आप इसे बाहर निकालकर पहन सकती हैं या अंदर से टक कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

**बैकलेस टॉप-** बैकलेस टॉप बहुत ही ट्रेंड में हैं, जो फूलों वाली स्कर्ट के साथ सबसे सुंदर लग सकते हैं। इसके लिए आप पश्चिमी शैली वाले टॉप चुन सकती हैं या फिर देसी शैली वाले डिजाइनर बैकलेस टॉप भी पहन सकती हैं। लंबी और मिडी, दोनों तरह की स्कर्ट के साथ ऐसे टॉप अच्छे लग सकते हैं। इन दिनों कैमी वाले बैकलेस टॉप भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। टॉप की फिटिंग और स्टाइल अपने हिसाब से चुन सकती हैं।

**ट्यूब या टैंक टॉप-** इन दिनों महिलाओं को फूलों वाली स्कर्ट के साथ जो टॉप पहनना सबसे ज्यादा पसंद है, वे हैं ट्यूब या टैंक टॉप। ट्यूब टॉप बिना बाजु और कंधे वाले टॉप होते हैं, जो काफी ट्रेंडी लुक प्रदान करते हैं। आप हल्के रंग वाली स्कर्ट के साथ हल्के रंग वाले ट्यूब टॉप का मेल बैठा सकती हैं, जो गर्मी के लिए आदर्श रहेगा। इसके अलावा टैंक टॉप हर महिला के पास होते ही हैं, जो इस स्कर्ट पर जंचते हैं।

**ऑफ शोल्डर टॉप-** अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर फूलों वाली स्कर्ट पहन रही हैं तो ऑफ शोल्डर टॉप बढ़िया चुनाव हो सकते हैं। इससे एक ट्रेंडी लुक मिल जाता है और आप सभी का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। आप दोनों तरफ से ऑफ शोल्डर या वन ऑफ शोल्डर टॉप चुन सकती हैं, जो भी आपको ज्यादा पसंद आए। इसके अलावा इन दिनों ऑफ शोल्डर टी-शर्ट भी काफी चलन में हैं, जिन्हें स्कर्ट के साथ स्टाइल किया जा सकता है।

**हॉल्टर नेक टॉप-** हॉल्टर नेक टॉप पिछले कुछ सालों से महिलाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। इन्हें गर्दन पर बांधकर पहना जाता है और इनकी नेकलाइन बेहद शानदार लुक देती है। इन्हें फूलों वाले प्रिंट वाली स्कर्ट के साथ पहनकर आपको सबसे सुंदर लुक मिलेगा, जो बीच पर जाने के लिए भी अच्छा रहेगा। टॉप की फिटिंग का खास ध्यान रखें, ताकि आपका लुक ज्यादा सुंदर नजर आए। हल्की एक्सेसरीज के साथ लुक को पूरा करें।

## वजन घटाने के लिए रस्सी कूदते समय न करें ये गलतियां, नहीं नजर आएंगे परिणाम

रस्सी कूदना एक असरदार एक्सरसाइज है, जो वजन घटाने में मदद कर सकता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं करते, जिससे उन्हें मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाते। इस लेख में हम कुछ आम गलतियों पर चर्चा करेंगे, जो लोग रस्सी कूदते समय करते हैं और यह भी जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। ये ध्यान देने वाली बातें जानकर आप अपनी एक्सरसाइज को अधिक असरदार बना सकते हैं और जल्दी वजन घटा सकते हैं।

**गलत लंबाई की रस्सी का चयन करना-** रस्सी कूदते समय सही लंबाई का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर रस्सी बहुत लंबी होती है तो इसे घुमाना मुश्किल हो जाता है और इससे कूदने में परेशानी होती है। वहीं, अगर रस्सी बहुत छोटी होती है तो इसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। अपनी ऊंचाई के अनुसार सही लंबाई की रस्सी चुनें, ताकि आप आराम से कूद सकें और एक्सरसाइज का पूरा लाभ भी उठा सकें।

**गलत प्रकार की रस्सी का उपयोग-** रस्सी का प्रकार भी बहुत अहम होता है। प्लास्टिक की रस्सी फिसलन भरी होती है, जिससे चोट लगने का खतरा रहता है। वहीं, मोटी रस्सी भी सही नहीं रहती, क्योंकि इससे कूदना मुश्किल हो जाता है। बेहतर होगा कि आप हल्की और मजबूत रस्सी का चयन करें, जो आसानी से घूम सके और फिसले नहीं। इसके अलावा रस्सी की पकड़ पर भी ध्यान दें, ताकि हाथों से फिसले नहीं और आप आराम से कूद सकें।

**गलत गति बनाए रखना-** रस्सी कूदते समय गति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत तेजी से कूदते हैं तो इससे थकान जल्दी हो सकती है और एक्सरसाइज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वहीं, अगर धीमी गति से कूदते हैं तो इससे कूदने का मजा कम हो जाता है और परिणाम भी संतोषजनक नहीं मिल पाते। सही गति बनाए रखें, ताकि आप आराम से कूद सकें और एक्सरसाइज का पूरा फायदा उठा सकें।

**गलत तरीके से कूदना-** रस्सी कूदते समय सही तरीका अपनाना आपको फायदे दे सकता है। हाथों को ज्यादा ऊपर-नीचे न करें, बल्कि कूदते समय केवल कंधों तक ही हाथों को उठाएं। इसके अलावा पैरों को भी ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत नहीं होती, बस जमीन से हल्का-सा ही उठाएं, ताकि रस्सी आसानी से नीचे आ सके। इससे न केवल आपकी एक्सरसाइज अधिक असरदार बनेगी, बल्कि चोट लगने का खतरा भी कम होगा और आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

## हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू की पहली झलक जारी, चौंकाएगा अभिनेत्री का अंदाज

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी पर्दे पर हमेशा अलग-अलग तरह के किरदार निभाने में विश्वास रखती हैं। उनकी आगामी फिल्म बेबी डू डाई डू में कुछ ऐसा ही नजर आया है, जिसकी पहली झलक जारी हो गई है। नचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित और सलीम सिब्लिंग्स (हुमा और साकिब सलीम) द्वारा निर्मित फिल्म में हुमा को बेबी करमारकर के किरदार में पेश किया गया है। वीडियो से पता चलता है कि अभिनेत्री इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका निभा रही हैं।

बेबी डू डाई डू का टीजर एनिमेटेड वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें मुंबई में लगातार होने वाली हत्याओं से जुड़े रहस्यमयी हत्यारे की तलाश को दिखाया गया है। पुलिस और मीडिया रहस्यमयी व्यक्ति की तलाश में व्यस्त है। दूसरी ओर एक महिला लाल छता लिए शहर में चुपचाप घूमती हुई नजर आती है। हैरानी की बात यह है कि महिला के छते में एक बंदूक छिपी है, जिससे वह दिन-दहाड़े लोगों का खून करती है।

हुमा ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर जारी किया है और कैप्शन दिया, आ गई अपनी फीमेल हिटवुमन! इससे पहले उन्होंने फिल्म के कई सारे पोस्टर साझा करते हुए फैंस को उत्साहित कर दिया था। निर्माताओं का कहना है कि फिल्म का टीजर जल्द जारी किया जाएगा। फिल्म में सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा,



विद्या मालवदे और हिमांशु मलिक जैसे सितारे भी नजर आएंगे। यह 3 जुलाई, 2026

को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

## सरगुन मेहता ने स्टाइलिश गाउन में बिखेरा ग्लैमर!



सरगुन मेहता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बना दिया है। इन फोटोज में एक्ट्रेस पर्पल कलर के स्टाइलिश गाउन में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं।

सरगुन मेहता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एक्ट्रेस अक्सर अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ नई शानदार फोटोज शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लेटेस्ट तस्वीरों में सरगुन पर्पल कलर के स्टाइलिश गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनका ये ग्लैमरस लुक देखकर फैंस नजर नहीं हटा पा रहे हैं। सटल मेकअप और स्ट्रेट हेयर के साथ उनका लुक और भी एलिगेंट लग रहा है।

सरगुन ने कैमरे के सामने अलग-अलग पोज देते हुए अपने कॉन्फिडेंट अंदाज से सभी का दिल जीत लिया है। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर प्यार बरसाना शुरू कर दिया। कमेंट सेक्शन में लोग उनकी खूबसूरती और स्टाइल की खूब तारीफ कर रहे हैं। सरगुन ने अपनी इन तस्वीरों से सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है। एक फैन ने लिखा, सोना कुड़ी। वहीं दूसरी ने कमेंट किया, क्वीन।

## नई टिहरी की जाम नालियां बढ़ा रही मानसून में जलभराव का खतरा

नई टिहरी (आरएनएस)। मानसून से निपटने के लिए नगर पालिका नई टिहरी की तैयारियां फिलहाल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। एक ओर नगर क्षेत्र में करोड़ों की धनराशि खर्च कर इन दिनों नगर पालिका सड़कों का डामरीकरण करवा रही है वहीं दूसरी ओर सड़कों के किनारे बनी नालियां कूड़े-कचरे और मलबे से अटी पड़ी हैं। कई स्थानों पर नालियां पूरी तरह बंद हैं। ऐसी स्थिति में मानसून की पहली बारिश का पानी सड़क किनारे स्थित घरों व दुकानों में घुसने का खतरा बना हुआ है। नगर पालिका इन दिनों करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से नगर क्षेत्र की 18 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण करा रही है लेकिन बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियों की सफाई और मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रही है। नगर क्षेत्र के मोलधार, आंचल डेयरी, जेल रोड, ऑल सेंट कॉन्वेंट स्कूल और जिला अस्पताल बौराड़ी के आसपास कई स्थानों पर नालियां लंबे समय से बंद पड़ी हैं। नालियों में जमा कूड़ा-कचरा और मलबा पानी की निकासी में बाधा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान नालियां ओवरफ्लो होने का खतरा बना रहता है। यदि समय रहते नालियों की सफाई नहीं हुई तो बारिश का पानी सड़कों पर बहने के साथ ही आसपास के मकानों और दुकानों के अंदर घुस सकता है। लोग नगर पालिका से नालियों की सफाई और मरम्मत की मांग करते आ रहे हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी है।

## कांवड़ मेले में उद्यमियों को नहीं मिलेगा हेतमपुर पुल का लाभ

हरिद्वार (आरएनएस)। कांवड़ मेले के दौरान उद्योगिक क्षेत्र सिडकुल, बहादुराबाद, सलेमपुर और हरिद्वार के करीब 1200 उद्योगों को हेतमपुर नए पुल का लाभ इस साल भी नहीं मिल सकेगा। कांवड़ के दौरान भारी वाहनों के लिए हाईवे बंद रहता है। उद्योगों में कच्चा माल समय से नहीं पहुंचता है। उद्योगों से उत्पादन माल की सप्लाई रुक जाती है। कांवड़ के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सौ फीसदी बंद हो जाता है। वहीं, हाईवे बंद होने से अन्य सेक्टर के उद्योगों को 50 फीसदी तक नुकसान उठाना पड़ता है। कांवड़ मेला अवधि में हाईवे पर वाहनों की आवाजाही करीब 15 दिनों के लिए बंद रहती है। कांवड़ के शुरुआती दिनों में रात 12 बजे से सुबह चार बजे तक पुलिस प्रशासन भारी वाहनों की आवाजाही के लिए हाईवे को खोलता है, लेकिन कांवड़ के आखरी आठ दिनों में हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन पूर्ण बंद कर दिया जाता है। हाईवे बंद होने के बाद रूट डायवर्ट रहता है। भारी वाहनों का संचालन टप होने के बाद उद्योगों में माल की आवाजाही बाधित होती है। कांवड़ के दौरान केवल फार्मा उद्योग से जुड़ी कंपनियों में 50 फीसदी उत्पादन जारी रहता है।

## ग्राम विकास और उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

अल्मोड़ा (आरएनएस)। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के प्रथम अल्मोड़ा प्रवास पर सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने की। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री गंगा बिष्ट, मेयर अजय वर्मा, नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख त्रिलोक रावत, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक, दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश खोलिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। अपने संबोधन में महेश नयाल ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम विकास से जुड़ी अनेक चुनौतियां हैं, जिनके समाधान की जनता को अपेक्षा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ग्राम्य विकास तथा लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभागों की जिम्मेदारी भरत सिंह चौधरी को सौंपे जाने

से ग्रामीण विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिलेगी। दर्जा राज्य मंत्री गंगा बिष्ट ने कहा कि गांवों का समग्र विकास ही राज्य के विकास का आधार है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेयर अजय वर्मा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका राष्ट्रवादी चिंतन और अखंड भारत का संकल्प आज भी प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि उनके सिद्धांतों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। मुख्य अतिथि भरत सिंह चौधरी ने कहा कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होने का गौरव इसलिए भी विशेष है क्योंकि पार्टी समाज और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

है। महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से गांवों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, जबकि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित कर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला बनाना है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री प्रकाश भट्ट ने किया जबकि समापन पर नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में किरण पंत, पूनम पालीवाल, कमला तिवारी, निशा बिष्ट, दीपिका बिष्ट, भावना पांडे, सौरभ वर्मा, मनीष जोशी, मनोज जोशी, पंकज भाकुनी, नीरज सांगा, चंदन बहुगुणा, आशीष डोगरा, अभिषेक तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

## खत्याड़ी की शत्रु संपत्तियों की 3 जुलाई को होगी ई-नीलामी

अल्मोड़ा (आरएनएस)। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि अभिरक्षक शत्रु संपत्ति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-नीलामी कार्यक्रम (08/2026) के अंतर्गत नगर पालिका खत्याड़ी, तहसील सदर स्थित शत्रु संपत्तियों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संपत्तियों की नीलामी जैसा है जहां है, जैसा है जो है तथा जो कुछ है के आधार पर एमएसटीसी पोर्टल पर की जाएगी। ई-नीलामी 3 जुलाई को प्रातः 11 बजे से शुरू होकर सायं 4 बजे तक आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत, सभी उपजिलाधिकारियों तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-नीलामी के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाए, ताकि अधिकाधिक इच्छुक व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकें।

## युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार

बागेश्वर (आरएनएस)। कांग्रेस जिला इकाई की बैठक में नीट पेपर लीक, भर्ती घोटालों पर चिंता जताई गई। कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता भाजपा की कार्यशैली से ऊब चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जनता देने को तैयार है। पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का जिले में जल्द कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें बुध लोकर एजेंट व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सभी ने एक स्वर से कहा कि जिस व्यक्ति को भी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। कार्यकर्ता एकजुट होकर उसे जिताने के लिए दिन-रात मेहनत करेंगे। प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों से आम लोग परेशान हैं। कार्यकर्ता जन विरोधी नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने की।

## खेत बचाओ अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने किसानों को किया जागरूक

अल्मोड़ा (आरएनएस)। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा के निदेशक डॉ. लक्ष्मी कांत के मार्गदर्शन में संस्थान के वैज्ञानिकों की पांच टीमों ने %खेत बचाओ अभियान% के अंतर्गत अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित पोषक प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा सतत कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करना था। अभियान में कुल 85 किसानों ने भाग लिया, जिनमें 55 महिला और 30 पुरुष किसान शामिल रहे। नैनीताल जिले के धारी क्षेत्र के लदफोड़ा मल्ला, लदफोड़ा तल्ला, सरना, अक्सोड़ा और हरिनगर सारना गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन, समेकित पोषक प्रबंधन, गोबर खाद, वर्मा कम्पोस्ट, हरी खाद तथा प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

## मासिक अपराध गोली में साइबर अपराध, यातायात और आपदा प्रबंधन पर फोकस

अल्मोड़ा (आरएनएस)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर. घोड़के की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी एवं सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

बैठक में अपराध नियंत्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम, पर्यटन सीजन में यातायात व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एसएसपी ने ग्राम प्रहरियों के साथ समन्वय बढ़ाने, बीट बुक अद्यतन रखने तथा आमजन से संवाद मजबूत करने के निर्देश दिए। आपदा सीजन को देखते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र में युवाओं के समूह गठित कर राहत एवं बचाव कार्यों में जनसहयोग लेने

को कहा गया। लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए गए।

पर्यटन सीजन के मद्देनजर ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग, बिना नंबर प्लेट, नाबालिग चालकों और रेडो साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, साइबर जागरूकता अभियान चलाने तथा एमआरएम पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में महिलाओं एवं नाबालिगों से जुड़े मामलों में संवेदनशील कार्रवाई, वांछित

अपराधियों की गिरफ्तारी, जीरो एफआईआर और ई-जीरो एफआईआर के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। साथ ही सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम मोबाइल फोन की बरामदगी और साइबर ठगी के मामलों में धनराशि होल्ड कराने के निर्देश दिए गए। थाना देघाट में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज बिष्ट को 54.45 किलोग्राम अवैध गांजा बरामदगी और दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सराहनीय योगदान के लिए मई 2026 का एमप्लॉयी ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सू-दोकू क्र.069									
	2			6					1
3				4					2
									6
6						4			
	9			5				6	1
4	3					9			2
	8			2					7
1		2				4		9	6

नियम									
1. कुल 81 वर्ग है, जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।									
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।									
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।									

सू-दोकू क्र.68 का हल									
8	7	6	9	5	1	2	3	4	
1	3	9	2	8	4	5	6	7	
4	5	2	3	7	6	9	1	8	
2	8	5	4	6	7	1	9	3	
3	1	7	8	9	2	4	5	6	
6	9	4	1	3	5	7	8	2	
9	4	1	6	2	8	3	7	5	
7	2	8	5	1	3	6	4	9	
5	6	3	7	4	9	8	2	1	



## गोर्खाली सुधार सभा की शहर शाखा का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न

संवाददाता

देहरादून। गोर्खाली सुधार सभा की शहर शाखा का वार्षिक अधिवेशन कर्मठ शाखा अध्यक्ष नरेश गुरूंग की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम शाखा अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा, महामंत्री गोपाल क्षेत्री, उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा सुब्बा चंद एवं मीडिया प्रभारी प्रभा शाह का स्वागत अभिनंदन किया। तत्पश्चात् उन्होंने शाखा के विगत वर्ष के कार्यों एवं आय-व्यय का सम्पूर्ण लेखा जोखा का ब्यौरा दिया। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने शाखा के मेधावी छात्र छात्राओं हिमानी क्षेत्री व निहारिका क्षेत्री को छात्रवृत्ति प्रदान की। आज इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु सभा की ओर से सुश्री दिव्या खत्री को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। इस अवसर पर शाखा के नंदकिशोर क्षेत्री एवं अनुराज क्षेत्री ने अपने विचार रखे। केंद्रीय पदाधिकारियों ने गोर्खाली सुधार सभा के कार्यों, उपलब्धियों एवं आगामी योजनाओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया। केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने शाखा अध्यक्ष नरेश गुरूंग एवं शाखा के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभा अपनी भाषा, संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ सबसे प्रमुखता में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, मेधावी छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होने में प्राथमिकता से सहयोग करती है। इस अवसर पर शाखा उपाध्यक्ष संजय थापा, अनुराज क्षेत्री, नंदकिशोर क्षेत्री, बृज मोहन क्षेत्री, श्रीमती रीमा ठाकुर, जितेन्द्र थापा, श्रीमती मनमाया देवी, दिल बहादुर, तुषार थापा, पिताम्बर क्षेत्री, जीत बहादुर थापा, राजेंद्र थापा शाखा के महानुभाव जन उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष जी द्वारा शाखा के इन मेधावी छात्र छात्राओं जोनिता शर्मा, शौर्य थापा, वर्षा राई को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। आज इस अवसर पर जान शाखा द्वारा श्रीमती ज्योति कोटिया (दर्जाधारी राज्यमंत्री) अध्यक्ष गोरखा कल्याण परिषद को सम्मानित भी किया गया।



## 4098 बालिकाओं को मिले 19.23 करोड़!

संवाददाता

देहरादून। उत्तरकाशी जनपद की 4098 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से इन बालिकाओं के बैंक खातों में करीब 19.23 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 2025-26 में प्रदेश की 33,251 पात्र बालिकाओं को 26 फरवरी 2026 को ही योजना का लाभ दिया जा चुका था। हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की कुछ पात्र बालिकाओं की आवश्यक औपचारिकताएं एवं जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण उन्हें उस समय लाभ नहीं मिल पाया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद यमुना कॉलोनी स्थित कैप कार्यालय में इन 4098 बालिकाओं को योजना की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे। नंदा गौरा योजना बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहल है। आज लाभान्वित बालिकाओं में जन्म के समय सहायता पाने वाली 417 बालिकाएं और 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक में प्रवेश लेने वाली 3681 बालिकाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक प्रदेश की कुल 4,11,035 बालिकाओं को करीब 1314 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा चुकी है।

# जनता 'बेफिक्र' और नेता हुए तैयार

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय भले शेष हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिगुल समय से पहले बजता दिखाई देने लगा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी राजनीतिक दल मिशन मोड में आ गए हैं। गांवों, कस्बों और शहरों में संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों को पता है कि पहाड़ की राजनीति में चुनावी फसल एक दिन में नहीं उगती, उसके लिए वर्षों पहले बीज बोने पड़ते हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचने का सपना देख रही है। इसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से लेकर सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्रीय दौड़ों की संख्या बढ़ गई है। सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भाजपा की कोशिश है कि सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मुद्दे में बदला जाए और सत्ता विरोधी लहर की संभावनाओं को शुरुआत में ही नियंत्रित कर लिया जाए।

वहीं कांग्रेस भी लंबे समय बाद सत्ता में वापसी का अवसर तलाश रही है। पार्टी ने नेतृत्व संगठन को मजबूत करने और गुटबाजी को नियंत्रित करने की चुनौती से जूझ रहा है। प्रदेश कांग्रेस की

- समय से पहले चुनावी मोड में आ गए दल
- भाजपा बूथों को मजबूत करने में जुट गई
- कांग्रेस संगठन खड़ा करने की कवायद में
- क्षेत्रीय दल तलाश रहे अपने लिए नई जमीन

बैठकों में लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जाए और भाजपा सरकार के खिलाफ जनमुहूर्तों को धार दी जाए। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य सेवाएं और भर्ती घोटाले कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिक हथियार बनते दिखाई दे रहे हैं।

क्षेत्रीय दल भी चुनावी समीकरणों में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटा है। राज्य आंदोलन की भावना और क्षेत्रीय अस्मिता को फिर से राजनीतिक मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसके अलावा नई राजनीतिक ताकतें और छोटे दल भी चुनावी समीकरणों में जगह बनाने के लिए सक्रियता बढ़ा रहे हैं।

2027 का चुनाव केवल सरकार और विपक्ष के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह संगठन क्षमता और जनसंपर्क का भी बड़ा इम्तिहान होगा। पिछले दो चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग

हैं। दस वर्षों की सत्ता के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। वहीं विपक्ष को भी महसूस हो रहा है कि यदि अभी से तैयारी नहीं की गई तो चुनाव के समय बहुत देर हो जाएगी।

दिलचस्प यह है कि अभी तक किसी भी दल ने आधिकारिक रूप से चुनावी अभियान की घोषणा नहीं की है, लेकिन नेताओं की सक्रियता, लगातार हो रही बैठकों, सदस्यता अभियानों और क्षेत्रीय दौड़ों ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि सभी दल चुनावी मोड में प्रवेश कर चुके हैं। जनता के बीच पहुंचने की होड़ शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं।

राजनीति के जानकार कहते हैं कि उत्तराखंड में चुनाव केवल रैलियों और नारों से नहीं जीते जाते। यहां गांव की चौपाल, स्थानीय मुद्दे और व्यक्तिगत संपर्क बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि सभी दल अभी से अपने संगठन को धार देने और जनता के बीच पैठ मजबूत करने में जुट गए हैं। फिलहाल तस्वीर साफ है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों की घड़ियां 2027 पर सेट हो चुकी हैं। प्रदेश की राजनीति अब विकास, आरोप-प्रत्यारोप और जनसंपर्क अभियानों के बीच नए चुनावी अध्याय की ओर बढ़ रही है। मिशन 2027 की शुरुआत हो चुकी है और अब हर राजनीतिक कदम का लक्ष्य केवल एक है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना।

## नशीले इंजेक्शनों सहित एक दबोचा

हमारे संवाददाता

नैनीताल। पर्यटन नगरी नैनीताल में नशा तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से 24 नशीले इंजेक्शन बरामद किये गये हैं। जानकारी के अनुसार बीते रोज थाना मुखानी पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कोई नशा तस्कर नशीले सामान की डिलीवरी हेतु आने वाला है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया। पुलिस ने जब उसे रूकने का इशारा किया तो वह सकपका कर भागने लगा। इस पर उसे घेर कर दबोचा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 24 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपना नाम चंचल सक्सेना उर्फ चन्दू पुत्र बाबू सक्सेना निवासी रैंबो पब्लिक स्कूल के पास नारायण नगर कुसुमखेड़ा मुखानी जनपद नैनीताल बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्जकर उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

## रुद्रप्रयाग की घटना को उक्राईन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

संवाददाता

देहरादून। रुद्रप्रयाग गुरुद्वारे वाली घटना को उक्राईन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

आज जिला रुद्रप्रयाग के नगरासू क्षेत्र में गुरुद्वारे वाली घटना को लेकर कड़ा रोष जताते हुए उत्तराखंड क्रांति दल जिला उत्तरकाशी की ओर से केंद्रीय महामंत्री किरन रावत द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा लिया गया। किरन रावत ने कहा कि नगरासू में जिस प्रकार से निहंगों द्वारा गुंडागर्दी की गई, कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं उसके बावजूद भी उन्हें पुलिस की सुरक्षा में सम्मान पूर्वक जाने दिया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि उनके द्वारा गुरुद्वारे पर अवैध कब्जा करके तीर्थ यात्रियों को



बंधक बनाया गया तथा आम जनता में पथराव किया गया जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित भी हुए। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 155 जिसमें बंधक बनाए जाने के लिए सजा का प्रावधान है तथा दंगा भड़काने के लिए एवं पथराव किए जाने पर धारा 148 में मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए थे। किंतु इसके विपरीत उनका सम्मान

पूर्वक भेजा जाना कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। क्योंकि अभी आगामी पंजाब में तथा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है जिसके चलते कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। अर्थात् "फूट डालो राजनीति करो" किंतु उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करता है। उत्तराखंड क्रांति दल "अतिथि देवो भव" का पूर्णतः सम्मान करता है, किंतु यदि देवभूमि उत्तराखंड के सम्मान एवं अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसको आघात पहुंचाया जाएगा तो इसको माफ नहीं किया जाएगा एवं जो भी ऐसे राज्य विरोधी तत्वों को संरक्षण प्रदान करेंगे उनके विरुद्ध भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

देवभूमि उत्तराखंड की शांत वातावरण को यदि कोई सामाजिक तत्व खराब करने का प्रयास करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा।

## मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित



संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर लोकतंत्र के सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जी. एम. एस. रोड स्थित एक होटल में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके परिजनों का सम्मान करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता बचाने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया तथा संविधान

की मूल भावना को आघात पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस और संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हो सकी। उन्होंने सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनका योगदान वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान इन मूल अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया, किंतु देश की जागरूक जनता ने लोकतांत्रिक माध्यमों से इसका जवाब देते हुए लोकतंत्र की

पुनर्स्थापना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि को 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। साथ ही, आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके आश्रित जीवनसाथियों को विशेष पहचान-पत्र भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान किया कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान तथा राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए विकसित भारत और श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में सभी अपना योगदान दें। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया तथा उनके संघर्ष और योगदान का स्मरण करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जेशी, खजान दस, विधायक श्रीमती सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बिष्ट, भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल मौजूद थे।

## 2025 में 21 प्रतिशत पाँस्को तथा 31 प्रतिशत गंभीर अपराधों में हुई सजा

हमारे संवाददाता

देहरादून/काशीपुर। वर्ष 2025 में उधमसिंह नगर के न्यायालयों ने कुल 9165 अपराधिक मुकदमों का फैसला किया है तथा भारतीय दंड संहिता के गंभीर अपराधों (सत्र न्यायालय) वाले मुकदमों में 31 प्रतिशत 40 मुकदमों में सजायें हुई हैं। जबकि 91 मुकदमों में रिहाई हुई है। बालक/बालिकाओं के यौन उत्पीड़न के विशेष कानून पाँस्को के 21 प्रतिशत 27 मुकदमों में सजा हुई तथा 99 मुकदमों में रिहाई हुई। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने अभियोजन निदेशालय से वर्ष 2025 में मुकदमों में सजा व रिहाई सम्बन्धी विवरणों की सूचना मांगी थी। जिसके उत्तर में संयुक्त निदेशक अभियोजन उधमसिंह नगर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 65 से सम्बन्धित विवरण की फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है। नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय दंड संहिता के सत्र न्यायालय में विचारण योग्य गंभीर मुकदमों (हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आदि) के 150 मुकदमों निर्णीत हुये जिसमें 40 मुकदमों में सजा हुई है जबकि 91 मुकदमों में रिहाई हुई है अर्थात् अभियोजन व पुलिस अपराध के साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। इस अवधि में 19 ऐसे मुकदमों में क्वेश/दाखिल दफ्तर भी हुये है। सजा का प्रतिशत 31 प्रतिशत है।

अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय गंभीर मुकदमों में सजा का प्रतिशत 75 है। 2025 में ऐसे 542 मुकदमों निर्णीत हुये है जिसमें 351 मुकदमों में सजा हुई है तथा 114 मुकदमों में अपराध साबित नहीं हुये है व रिहाई हुई है। ऐसे 45 मामले दाखिल दफ्तर/क्वैश हुये है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2025 में अधीनस्थ न्यायालयों (मजिस्ट्रेटों आदि के न्यायालयों) में भारतीय दंड संहिता के अपराधों के 341 मामलों में सजा हुई है जबकि 126 मामलों में रिहाई हुई है। इस अवधि में 537 मुकदमों में राजीनामा हुआ है तथा 304 मामले दाखिल दफ्तर/क्वैश हुये है। सजा का प्रतिशत 73 प्रतिशत है। अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचारणीय मुकदमों में 2064 मामलों में सजा हुई है जबकि 83 मामलों में रिहाई हुई है। 1168 मामले दाखिल दफ्तर/क्वैश हुये है। सजा का प्रतिशत 96 प्रतिशत है।

## डीएम ने नारी निकेतन, बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का किया निरीक्षण

हमारे संवाददाता

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आज केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह एवं किशोरी गृह का स्थलीय निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवासीय संस्थानों में रह रहे बच्चों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता एवं पुनर्वास संबंधी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाल सुधार गृह में रह रहे बालकों से संवाद स्थापित कर उनकी दिनचर्या, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं की



जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल सुधार गृह में बेसिक लर्निंग प्रोग्राम संचालित किया जाए, जिससे बच्चों की शैक्षिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। साथ ही उन्होंने बाल सुधार गृह में निवासरत सभी बालकों का विस्तृत

प्रोफाइल तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि संस्थान में रह रहे प्रत्येक बालक की नियमित काउंसलिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायता मिल सके। उन्होंने बच्चों के पुनर्वास एवं

व्यक्तित्व विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी बल दिया। नारी निकेतन एवं किशोरी गृह के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नारी निकेतन में निवासरत किशोरियों एवं संवासिनियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तथा उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए संबंधित

अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वर्तमान में नारीनिकेतन में 160 संवासिनिया, बाल सुधार गृह में 07 किशोर, किशोरी संप्रेक्षण गृह में 12 किशोरिया है। निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष नमिता ममगाई, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज कुमार शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, सदस्य पीएन जौहर, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

## वेनेजुएला में भूकंप से 10 हजार से अधिक लोगों की मौत की आशंका, इमरजेंसी घोषित

संवाददाता

काराकास। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया है। एक मिनट के अंतराल में आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। कई इमारतों और मकानों के ढहने की खबर है। जिसमें 10 हजार से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस दक्षिण अमेरिकी देश में भारी जान-माल का नुकसान हो सकता है।

यू.एस. जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, काराकस से लगभग 160 किलोमीटर (100 मील) पश्चिम में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और एक

मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, मरने वालों की संख्या 10,000 से 1,00,000 के बीच हो सकती है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इमरजेंसी का एलान किया है। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने दुर्भाग्य से अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि, उन्होंने मरने

वालों या घायलों की कुल संख्या नहीं बताई।

भूकंप के बाद मदद से लिए



अमेरिका आगे आया है। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने र पर कहा, ष्टम वेनेजुएला के अधिकारियों के संपर्क में हैं और मदद जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप बहुत विनाशकारी

था। काराकस में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वह भूकंप के बाद की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और देश के नागरिकों से सुरक्षित आश्रय लेने और क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील की है। जिस दिन वेनेजुएला में भूकंप आया, उस दिन सार्वजनिक छुट्टी थी और लोग अपने घरों में थे। इसी दिन 1821 में स्पेन से वेनेजुएला को आजादी मिली, जिसके कारण इस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। वेनेजुएला के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भूकंप के झटकों का तुरंत कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि जिन शहरों में भारी नुकसान की आधिकारिक रिपोर्ट है, उनमें से लगभग किसी में भी महत्वपूर्ण तेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक

कांति कुमार

संपादक

पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक

आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:

वी के अरोड़ा, एडवोकेट

बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।